Tc.No.: GUJHIN00722

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 10 , शुक्रवार, 02 फरवरी 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

सार समाचार

दिल्ली पुलिस ने 12 साल के अपहृत लड़के को छुड़ाया, दो गिरफ्तार, मांगे थे 1 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में स्कूल से घर लौटते समय तीन दिन पूर्व अपहृत 12 वर्षीय एक लड़के को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है और अपहरण के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, आरोपियों में से एक तारीफ लड़के के पिता द्वारा संचालित फैक्टरी का कर्मचारी है, जबकि दूसरा आरोपी दानिश वहां काम किया करता था। गत सोमवार को लड़का अपनी बहन के साथ स्कूल से कर्दमपुरी स्थित अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि, आरोपियों ने लड़के से उसके संबंधी का पता पूछा और फिर उसे उठा कर ले गए। जिसके बाद लड़के के पिता को फोन आया और अपहरणकर्ताओं ने लड़के को छोड़ने के बदले एक करोड़ रुपये मांगे। ज्योतिनगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि, लड़के का चचेरा भाई अपहरण के पीछे कथित मास्टरमाइंड था।

यूपी: गुस्से में आया बिजली विभाग, हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई

शाहजहांपुर। बड़े बकायेदारो के खिलाफ बिजली विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कई सरकारी विभागों का लाखों रुपये बिजली का बिल बकाया है और अब उनका कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है। मानसिक चिकित्सालय का कनेक्शन बिजली विभाग ने काटकर अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस समय पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पीडब्ल्यूडी, सरकारी अस्पताल, नगर निगम, वन विभाग, पर्यावरण विभाग समेत कई सरकारी विभागों का करोड़ों रुपये बिजली का बिल बकाया है। अगर यह भुगतान हो जाए तो शहर में दो सबस्टेशन बनाए जा सकते हैं। बकायेदार कार्यालयों को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। अब इनका कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है।

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया गैरकानूनी बोरवेल सील करने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि राजधानी के सभी गैरकानूनी बोरवेलों को तीन महीने के भीतर सील किया जाए। शहर में बोरवेल के जरिए गैरकानूनी ढंग से पानी निकालने को लेकरचिंता प्रकट करते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से दायर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि राजधानी में ऐसे कई बोरवेल हैं जो प्रशासन की अनुमति के बगैर चल रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने राजस्व विभाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उसने पुलिस से कहा कि वे इस संदर्भ में जरूरी सहयोग प्रदान करे। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को यह निर्देश भी दिया कि दूषित पानी वाले बोरवेल को चिह्नित किया जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को लेकर पहले नगर निकायों को फटकार लगाई थी।

जिला जजों से नाराज हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के बारे में जिला जजों द्वारा उसे सूचना मुहैया किए जाने के कार्य को दयनीय बताया है। दरअसल, ये कैदी जमानत मंजूर हो जाने के बावजूद रिहा नहीं हो पा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की सदस्यता वाली एक पीठ ने कहा कि जिला जजों को जेल से रिहा होने के हकदार लोगों के बारे में आंकडे जुटाने और यह आकलन करने का निर्देश दिया गया था कि क्या उन लोगों की रिहाई से समाज को खतरा होगा।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ को जानकारी दी गई कि उपराज्यपाल ने केन्द्र के निर्देश पर प्राधिकरण का गठन किया है।

बजट में रेल: हाई स्पीड ट्रेनों की शुरूआत, शताब्दी-राजधानी की होगी विदाई

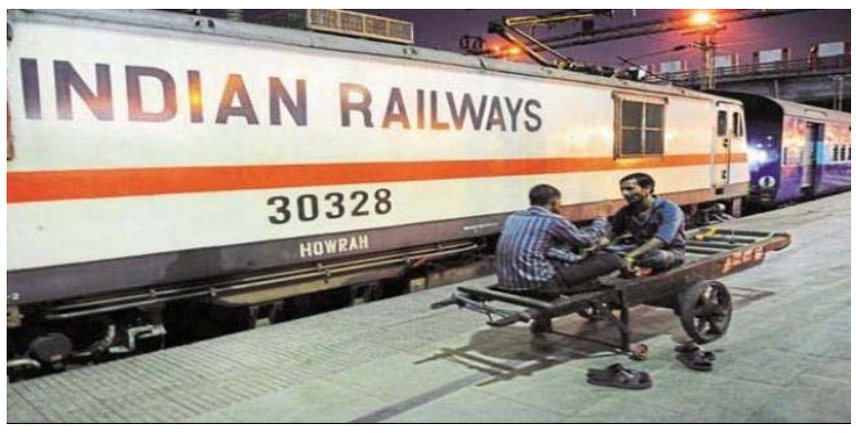

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 देश में हाई स्पीड ट्रेनों (ट्रेन सेट) की नींव रख दी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैसे एलएचबी व अल्मुमीनियम कोच से तैयार ट्रेन सेट मौजूदा रेलवे की प्रीमियम ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस व राजधानी एक्सप्रेस के स्थान पर चलाई जाएंगी। उन्होंने भारतीय रेल के संपूर्ण नेटवर्क को ब्राडगेज बनाने का ऐलान किया है। देश में अब हाई स्पीड ट्रेनों के युग की शुरूआत होने जा रही है।

जेटली ने रफ्तार बढ़ाने के अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ट्रेनों व स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।

सुविधाओं में इजाफा करते हुए समस्त ट्रेनों में वाईफाई, स्केलेटर, 600 स्टेशनों को पुर्नविकास, ऑनलाइन टिकट का विस्तार किया जाएगा। अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में रेलवे की वार्षिक योजना के लिए एक लाख 48 हजार 528 रुपये का प्रावधान किया है। इसका बड़ा हिस्सा रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। जिससे रेलवे की क्षमता में बढ़ोत्तरी हो सके और परंपरागत राजधानी-शताब्दी ट्रेनों के स्थान पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सकें।

रेलवे जून 2018 में शताब्दी की तर्ज पर ट्रेन सेट 18 ट्रैक पर उतार देगी। जबकि राजधानी की तर्ज पर ट्रेन सेट 20 दो साल बाद फर्राटा भरने लगेगी। जेटली ने कहा कि सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरूआत कर चुके हैं।

हाई स्पीड ट्रेन परिचालन के लिए गुजरात के गोधरा में प्रशिक्षण संस्थान मानव संसधान तैयार करेगा।

चैन्नई आईसीएफ में तैयार हो रही ट्रेन सेट रेलवे के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होगा। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में 18000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण, तिहरीकरण व चौथी लाइन बिछाई जाएगी। जबकि 5000 किलोमीटर पुराने ट्रैक के स्थान पर ब्राडगेज ट्रैक बिछाया जाएगा। हालांकि जेटली ने समूचे भारतीय रेल को ब्राडगेज बनाने की घोषणा की है। रेलवे की क्षमता विस्तार को आगे बढ़ाते हुए जेटली ने 2018-19 के लिए 12000 नए वैगन, 5160 नए कोच और 700 नए इंजनों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल की प्रशंसा में जेटली ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 4000 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण हो जाएगा। जबकि अगले साल के लिए 36000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। जिससे रेल फेक्कर होने की संभाना शून्य हो जाए और ट्रेन हादसे न हो। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्त मंत्री ने सभी ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।

प्रतिदिन 25000 यात्री के आवागमन वाले सभी स्टेशनों पर स्केलटर लगाए जाएंगे। सुरक्षित ट्रेन परिचलान के लिए जेटली ने फॉग सेफ डिवाइस को ट्रेनों मे लगाने की घोषणा की।

इसके साथ ही वर्षो से रेल हादसों को रोकने के लिए ट्रेन वार्निंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम (टीपीडब्ल्यूएस) लगाने का ऐलान किया है। टीपीब्ल्यूएस में ड्राइवर को सिग्नल देखने की जरुरत नहीं है वह इंजन के कैब में लगे स्क्रीन पर सिग्लन सिस्टम से ट्रेन चलाएगा।

रेल मंत्री विश्व स्तरीय सिग्नल सिस्टम लगाने की बात पहले कह चुके हैं।

काशी विद्यापीठ और संस्कृत विवि के कुलपतियों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा

वाराणसी। एक दूसरे को शुभकामनाएं देते काशी विद्यापीठ के कुलपति डा.पी.नाग और संस्कृत विवि के कुलपति प्रो.यदुनाथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति डॉ. पी. नाग और सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया गया है। दोनों कुलपतियों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो रहा था। लखनऊ के राजभवन की ओर दोनों परिसरों की कई दिनों से निगाहें लगी हुईं थी। दोनों कुलपतियों के स्थान पर अभी नए का चयन नहीं हो पाया है। बताते हैं, नये कुलपतियों की तलाश चल रही है। इस संबंध में कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। इन पर गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब विराम लग गया, जब राजभवन से दोनों कुलपतियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाने का संदेश फैक्स से मिला। राज्यपाल राम नाईक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नया कुलपति नियुक्ति होने में अभी समय लगेगा। इसलिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वर्तमान कुलपति का कार्यकाल तीन माह की अवधि या नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेश तक जो पहले हो, तक के लिए बढ़ाया जाता है। राजभवन का आदेश मिलते ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने डॉ. पी. नाग और प्रो. यदुनाथ दुबे को शुभकामनाएं दीं। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे खुद विद्यापीठ पहुंचे और डॉ. पी. नाग को बधाई दी। मीडिया से बातचीत में डॉ. पी. नाग ने कहा कि परिसर के विकास, समय से परीक्षा शुरू करने और नैक का निरीक्षण कराने की प्राथमिकता रहेगी। वहीं प्रो. यदुनाथ दुबे का कहना था कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को लेकर है। शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से वेतन मिले, इसके लिए प्रयास करेगे। इसके लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। परीक्षाएं भी समय से शुरू कराई जाएंगी।

मुरादाबाद में बजट को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, मिलीजुली रही प्रतिक्रिया

मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में बजट को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह दिखाई दिया। लोग टीवी, मोबाइल और रेडियो से चिपके रहे। हालाकि बजट आने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कोई बजट को बढ़िया बता रहा तो कोई बजट से खुश नहीं दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया। इससे मिडिल क्लास के उपर ही बोझ बढ़ेगा। यहीं नहीं मोबाइल और टीवी सस्ते होने चाहिए थे लेकिन इसे भी महंगा कर दिया गया है।

मुरादाबाद: कन्या भ्रूण हत्या कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 महिलाएं थी शामिल

मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले में कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दस लोगों के खिलाफ कन्या भ्रूण हत्या के आरोपों की पुष्टि का हवाला देकर कुंदरकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तमाम शिकायतें मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुंदरकी इलाके में सक्रिय गिरोह के बारे में पड़ताल कराई जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के आरोपों की तस्दीक हुई। विभाग ने इस मामले में कुंदरकी क्षेत्र के दस लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी है।

इनमें आठ महिलाएं हैं।

एफआईआर की तहरीर में रेशमा, आलमीन, रिहाना, लक्ष्मी सक्सेना, सीमा, फिरोज आलम, मुमताज बी, किरन, इमराना और नजमुल हसन को नामजद किया गया है। आरोप है कि ये सभी लोग कन्या भ्रूण हत्या के कृत्य में लिप्त हैं। आसपास स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मदद से इसे अंजाम दे रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग को पिछले कई महीने से इनके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जिसके आधार पर विभाग ने टीमें भेजकर जांच कराई।

जारी रहेगा जांच और कार्रवाई का सिलसिला

पीसीपीएनडीटी के जिला नोडल अधिकारी डा. रंजन गौतम ने बताया कि कुंदरकी क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से कन्या भ्रूण हत्या के अपराध में शामिल दस लोगों पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं में एफआईआर करा दी गई है। इन सभी पर बिना किसी डॉक्टरी डिग्री होते हुए चिकित्सा संबंधी कार्य करने का गंभीर आरोप भी है। इस संबंध में जितनी भी शिकायतें आएंगी। उनकी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला जारी रहेगा।

हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को इस मामले में जिला जजों, जेल महानिदेशक व अन्य से रिपोर्ट मांगा था।

पैसे के अभाव में जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं सैकड़ों कैदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जमानत मिलने के बाद भी मुचलका भरने के लिए पैसे के अभाव में जेल से कैदियों के रिहा नहीं होने के मामले में जिला जजों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि ऐसा लगता है कि न्यायिक अधिकारियों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किए बगैर ही रिपोर्ट तैयार किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को इस मामले में जिला जजों, जेल महानिदेशक व अन्य से रिपोर्ट मांगा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने यह आदेश तब दिया था जब केजरीवाल सरकार ने यह स्वीकार किया था कि राजधानी की विभिन्न जेलों में 318 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जमानत मिलने के बाद भी जिनकी रिहाई नहीं हुई है।

पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह निचली अदालत से मिली रिपोर्ट को वापस कर दे। साथ ही ठोस व तार्किक रिपोर्ट करने के लिए सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश अधवित्का अजय वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

हथियार तस्कर को मदद करने में एसएचओ निलम्बित

नई दिल्ली (एजेंसी)। हथियार तस्कर की कथित तौर पर मदद करने आरोप में विजय विहार थाने के एसएचओ दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले में आरोपी को विजय विहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी ही शिकायतकर्ता बनकर एचएचओ और एक एसआई की शिकायत सतर्कता विभाग में कर दी थी। जानकारी के अनुसार, बीते साल 14 सितंबर को प्रतीक शौकीन ने सतर्कता विभाग को शिकायत दी थी। शिकायत में प्रतीक ने कहा कि जुलाई में विजय विहार पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसे छोड़ने के लिए एसआई अनुज ने 15 लाख रुपये की मांग की। मगर, अंत में बात पांच लाख रुपये पर रुकी। आरोप है कि प्रतीक ने पत्नी और मां को थाने में बुलाकर रुपये एसआई को दिए। इसकी वजह से वह पुलिस की कमजोर पैरवी की वजह से जमानत पर बाहर आ गया। कुछ ही समय बाद प्रतीक ने एसआई से सम्पर्क कर मामले को खत्म करने की बात कही। दबाव बनाने पर एसआई ने एसएचओ दिनेश कुमार के सामने बात रखी। सूत्रों के अनुसार, एसआई ने केवल दो लाख रुपये के लेनदेन के बारे में एसएचओ को बताया था। इस वजह से प्रतीक को कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद प्रतीक ने सतर्कता विभाग में पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने की शिकायत कर दी।

इस बीच प्रतीक को उसके दो अन्य साथियों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने इस साल जनवरी में गिरफ्तार कर हथियार तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पूछताछ में मालूम हुआ कि वह विजय विहार पुलिस द्वारा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। वहीं, सतर्कता विभाग की प्राथमिक जांच में पाया गया कि प्रतीक का विजय विहार थाने की ओर से पक्ष लिया गया था। अगर स्थानीय पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती तो गिरोह का खुलासा पहले ही चुका होता। सतर्कता विभाग के निर्देश पर एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है।

चालक की वजह से पकड़ा गया शौकीन : बीते साल जुलाई में प्रतीक का ड्राइवर उसकी कार बिना बताए ही विजय विहार इलाके में आ गया। तभी कुछ लोगों ने उसकी कार लूट ली, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कार की तलाशी में अवैध हथियार मिलने पर पुलिस प्रतीक शौकीन तक पहुंच गई।

'डीयू विधि संकाय में एलएलबी की लगभग 700 सीटें हर साल बर्बाद होने का दावा

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विधि संकाय में एलएलबी की 500 से 700 सीटें हर वर्ष बर्बाद हो जाती हैं। हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ के समक्ष बुधवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन, न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब 5 फरवरी को मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष होगी।

हाईकोर्ट में डीयू विधि संकाय के लॉ सेंटर के दूसरे वर्ष के छात्र ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष 500 से 700 सीट बेकार चली जाती हैं क्योंकि या तो छात्र हॉस्टल की सीट सुरक्षित करने के लिए प्रवेश लेते हैं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक विकल्प के तौर पर एलएलबी की सीट को ब्लॉक कर देते हैं।

याचिकाकर्ता सुभाष विजयरन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऐसे में उन लोगों को दाखिला नहीं मिल पाता है जो वास्तव में कानून की पढ़ाई करके वकालत के पेशे में जाना चाहते हैं। उन्होंने याचिका में विश्वविद्यालय, विधि संकाय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों से पांच लाख रुपये का बांड या कोई भी उचित राशि अनिवार्य करने का निर्देश देने की मांग की है।

ममेरे भाई का अपहरण करा मांगे एक करोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर पूर्व जिला के ज्योति नगर इलाके में एक युवक ने साजिश रच कर अपने सगे मामा के बेटे का ही अपहरण करा डाला। अपहर्ताओं ने परिजनों से एक करोड़ रुपये की फिरौती भी मांग डाली। हालांकि पुलिस ने दोनों अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। डीसीपी एक सिंगला ने बताया कि दस साल के बच्चे का परिवार ज्योति नगर इलाके में रहता है। वहीं उसके पिता की इलाके में छोटी छोटी कई फैक्ट्रियां हैं। 29 जनवरी को बच्चा अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। तभी बाइक सवार दो युवक उसे रास्ते में मिले और उन्होंने बड़े पापा का घर दिखाने के लिए कहा। बच्चा उनके साथ बाइक पर बैठकर चला गया। देर रात परिजनों को फिरौती के लिए फोन आया तो मालूम हुआ कि बच्चे का अपहरण हो गया है। अपहरण की जानकारी होने पर परिजनों ने सावधानी पूर्वक पुलिस से सम्पर्क साधा।

सातवें फोन काल से हुई गिरफ्तारी

इसके बाद मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर एएटीएस विनय यादव की टीम गठित की गई थी। इस दौरान परिजनों को फोन कभी पानीपन तो कभी सोनीपत और 30 दिसम्बर की रात को फोन काल कैलाश नगर से की गई थी। मोबाइल सर्विलांस से बचने के लिए अपहर्ता फोन पीसीओ से कर रहे थे। इस तरह उन्होंने सात बार फोन किया था। इन्होंने पांचवां, छठां और सातवीं बार फोन कैलाश नगर से किया था। इसलिए पुलिस इस इलाके में फैल गई और यहीं से तारिक और दानिश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि बच्चे के पिता के सगे भांजे मोहसिन ने अपहरण की साजिश रची थी।

मोलभाव में मिला समय

फोन कर अपहर्ताओं ने एक खोखा यानी एक करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन बच्चे के पिता ने असमर्थता जताई और सातवीं काल में बात पांच लाख रुपये पर आ गई। इसपर तारिक ने कहा कि बॉस से पूछकर बताते हैं। यह जानकारी मिलने पर पुलिस भी समझ गई कि ये लोग कैलाश नगर इलाके में ही होंगे। पुलिस की टीम इलाके में फैल गई। इसी दौरान इंस्पेक्टर एशवीर सिंह की टीम रामलीला मैदान की तरफ अंधेरे इलाके में गई तो देखा कि एक बच्चे को लिए दो लोग खड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पहचान उजागर हो गई।

लगातार रख रहा था नजर

मोहसिन मूल रूप से बंदायूं का रहने वाला है और इस समय अपने मामा के पैसे पर पल रहा था। वह मामा की फैक्ट्री में काम करता था और उनका दायां हाथ था। रुपये की डिलवरी के दौरान जब दोनों युवकों न फोन नहीं उठाया तो उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए गिरफ्तारी के दौरान ही वह इलाके से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

दस हजार रुपये का लालच दिया

तारिक और दानिश पीड़ित के पिता की गोकलपुरी स्थित फैक्ट्री में काम करते हैं। एक दिन उन्होंने मोहसिन से दस हजार रुपये मांगे तो उसने अपहरण की साजिश रचकर उन्हें शामिल कर लिया। इन्होंने तीन से अपहरण की कोशिश शुरू कर दी थी।

आखिरकार सफलता उन्हें मिल गई। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपराध आधारित टीवी सीरियल देखकर आईडिया लिया।

तीन चीजें किसी भी इन्सान को बरबाद कर सकती है -शराब, घमंड और क्रोध -अज्ञात

''राष्ट्र मंच'

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करके अपने को प्रासंगिक बनाने की कवायद में जुटे भाजपा के विद्रोही नेता यशवंत सिन्हा और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ''राष्ट्र मंच' के गठन की घोषणा करके अपने आप को पूरी तरह अप्रासंगिक बना लिया है। भाजपा के नेता द्वय ने यह दावा किया है कि यह गैर-राजनीतिक मंच है, और देश के ज्वलंत मुद्दों को जनता तक ले जाने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए आंदोलन का काम करेगा। लेकिन हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, और उनकी नीतियों को जन समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उनका नवगठित ''राष्ट्र मंच' राष्ट्रीय संवाद को प्रभावित कर पाएगा, इसकी कोई संभावना दूर-दूर तक दिखाईनहीं देती। हां, इतना जरूर है कि विपक्षी दल अपने हितों के लिएइस मंच का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहेगा। लोगों को याद होगा कि पिछले साल यशवंत सिन्हा ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत, मोदी सरकार के विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे साहसिक फैसलों को जनसमर्थन मिला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव इसके पुख्ता प्रमाण हैं। दरअसल, यशवंत सिंह मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति के मुखर आलोचक हैं। अटल बिहारी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वह इन दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति की सराहना तो की जा सकती है, लेकिन यह सच है कि आर्थिक मोर्चे पर वह अब तक खरी नहीं उतर पाईहै। किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। वित्त मंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई कम नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके अगर सरकार का इकबाल बना हुआ है, तो इसकी मुख्य वजह विपक्ष की अदूरदर्शिता है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके ''जनमोर्चा' का गठन किया था, लेकिन उनके पास राजनीतिक एजेंडा और जनसमर्थन, दोनों था। अलबत्ता, वह देश के समक्ष एक विकल्प लेकर आए और सफल भी रहे। सवाल है कि क्या यशवंत सिन्हा ऐसा कोईविकल्प लेकर सामने आएंगे? अगर नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के समक्ष वह शायद ही कोईचुनौती पेश कर पाएं। सच तो यह है कि बजरंग दल, हिन्दू वाहिनी जैसे समूह सरकार के लिए ज्यादा परेशानियां पैदा कर रहे हैं।

भाजपा के बीच तलवारें

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में तीन लोगों की मौत से सूबे का माहौल एक बार फिर गरमा गया है। राज्य पुलिस ने सेना की गढ़वाल इकाई के 10 सैन्यकर्मियों-जिनमें एक मेजर भी शामिल हैं-के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और धारा 307 (हत्या के प्रयास) का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मसले पर राज्य की सत्ता में प्रमुख साझीदार पीडीपी और भाजपा के बीच तलवारें खिंच गई है। पीडीपी जहां इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की बात कह रही है वहीं भाजपा किसी भी हालत में सेना के खिलाफ मुकदमेबाजी का आक्रामक तरीके से विरोध कर रही है। यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर जम्मू-कश्मीर की सरकार गिराने की बात तक कह दी है। यकीनन राज्य में सियासी हालात फिर अस्थिर होता दिख रहा है। हालांकि पूर्व में भी पीडीपी और भाजपा के बीच तनातनी होती रही है मगर इस बार मामला मुख्यमंत्री के एफआईआर दर्ज कराने की हड़बड़ी की वजह से कहीं ज्यादा खराब होता दिख रहा है। और यही बात राज्य सरकार में भागीदार रही भाजपा के लिए परेशानी और गुस्से का सबब है। अलबत्ता, यह पहला मौका नहीं है जब गठबंधन सरकार के ही घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। इससे पहले मेजर लिटुल गोगोई के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच रिश्ता तल्ख हुआ था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सेना की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई थी। इस मामले में भी रक्षा मंत्रालय अपने मेजर का बचाव करती दिख रही है। वह यह कहकर सेना की कार्रवाई का बचाव कर रही है कि आत्मरक्षा में सैनिकों को पत्थरबाजों पर गोली चलानी पड़ी। कहीं-न-कहीं केंद्र सरकार को यह महसूस होता है कि सैन्यकर्मियों पर मुकदमा लिखे जाने और जांच की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से उसके मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा वह संयत तरीके से मसले को समझ रही है। जहां तक कश्मीर के वर्तमान हालात की बात है तो इस तय से हर कोई मुतमईन होगा कि वहां अमन बहाली के रास्ते कितने टेढ़े-मेढ़े हैं। चुनांचे सरकार और सेना, दोनों को संजीदा होकर आगे बढ़ना होगा।

सत्संग

संसार

अपना ज्ञान जो दुनिया से सीखा था, वास्तव में मैं बराबर आपसे बोलता रहा हूं रात भर आपसे बात करता रहा हूं। आप सोये रहे हैं और मैं आपके सिरहाने बैठा-बैठा आपको थपकियां लगाता रहा हूं, लोरियां सुनाता रहा हूं, मोहब्बत के गीत सुनाता रहा हूं। न जाने क्या से क्या कहता रहा हूं और मैंने बहुत खुशामद की है आपकी। इंसानो! मेरे मित्रो! तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्या? तुम मुझे केवल गुरु जी, आशीर्वाद देने वाले ही मानते रहोगे क्या? मैं जलता हुआ इंसान हूं और मैं सही इन्सान हूं। क्या तुम जलते हुए इंसान नहीं बन सकते? क्या भगवान की लौ में समाने के लिए, लोगों के अंदर लौ की आग, ज्ञान की आग पैदा नहीं कर सकते। न जाने मैं क्या से क्या कहता रहा हूं? मेरी चारों वाणियां (परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी) बोलती रही हैं। आपके हृदय से मैं बोलता रहा हूं। आत्मा से बोलता रहा हूं। कानों से बोलता रहा हूं। मस्तिष्क से बोलता रहा हूं। आप जाइए और आप मेरी आवाज को आज बांध कर के चले जाइए। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। जहां कहीं भी रहूंगा, बोलता रहूंगा और आपसे लड़ता रहूंगा। कहता रहूंगा। जैसे अभी इन चादरों में आप सोये रहे हैं, तब मैंने आपको बहुत कुछ कहा है। यह कहना उस वक्त बंद हो जाएगा, जब आप मेरी राह पर चलेंगे। उस राह पर, जिस राह पर मैं अपने गुरु के इशारे पर चला और मैंने अपनी जिंदगी सारी की सारी उनके कहने के मुताबिक ही खर्च कर डाली। मैं चाहता हूं आपका वक्त, उन कामों में खर्च हो। मैं चाहता हूं आपका पसीना, उन कामों में खर्च हो। मैं चाहता हूं आपका पैसा, उन कामों में खर्च हो। जिन कामों के लिए मैं जीया, जिन कामों के लिए मैं पैदा हुआ। जिन कामों में मैं ये कल्याण चाहता हूं, संसार का कल्याण देखता हूं और मानवता का उत्थान। इसीलिए छोटी साधना के रूप में मैं आपको दस पैसा रोज खर्च करने की बात कहता रहा, एक घंटे समय खर्च करने की बात कहता रहा। छोटी-छोटी बातें थी शुरुआत की। लेकिन ये तो शुरु आत है, जो मैं बहुत चाहता हूं, हर वक्त कहता हूं। अगले दिन आएंगे, जब आपको मेरे तरीके से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों पर समर्पित करना होगा और अपनी सारी की सारी चीजें समेट करके भगवान के पांवों पे लाकर रखनी पड़ेंगी, ताकि भगवान के पास जो कुछ है, उन सबको पाने के हकदार आप बन जाएं।

कारोबार लोगों को कर राहत की उम्मीद

सरकार ने करदाताओं के लिए राहत के संकेत भी दिए हैं। चूंकि अप्रत्यक्ष कर अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल किए जा चुके हैं, इनमें वृद्धि या कमी करने का फैसला केवल जीएसटी परिषद ही ले सकती है, इसलिए अप्रत्यक्ष करों में आमतौर पर होने वाले बदलाव अब नये बजट 2018-19 में नहीं दिखाई देंगे। चूंकि 2018-19 का बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इस कारण लोगों की बचत एवं उद्योग-व्यापार को गति देने के लिए विभिन्न कर राहत की संभावनाएं हैं। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर आयकर एवं कॉरपोरेट टैक्स में रियायत मिल सकती है ताकि खर्च करने योग्य आय में इजाफा किया जा सके और कारोबार को भी गति दी जा सके।

सतीश पेडणोकर

एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से करदाताओं खासतौर से छोटे आयकरदाताओं, नौकरीपेशा मध्यम वर्ग के साथ-साथ उद्योग एवं कारोबार क्षेत्र के लोगों को कर राहत की उम्मीद है। सरकार ने करदाताओं के लिए राहत के संकेत भी दिए हैं। चूंकि अप्रत्यक्ष कर अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल किए जा चुके हैं, इनमें वृद्धि या कमी करने का फैसला केवल जीएसटी परिषद ही ले सकती है, इसलिए अप्रत्यक्ष करों में आमतौर पर होने वाले बदलाव अब नये बजट 2018-19 में नहीं दिखाई देंगे। चूंकि 2018-19 का बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इस कारण लोगों की बचत एवं उद्योग-व्यापार को गति देने के लिए विभिन्न कर राहत की संभावनाएं हैं। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर आयकर एवं कॉरपोरेट टैक्स में रियायत मिल सकती है ताकि खर्च करने योग्य आय में इजाफा किया जा सके और कारोबार को भी गति दी जा सके। गौरतलब है कि छोटे आयकरदाता नौकरीपेशा वर्ग के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई और घटती हुई बचत के मद्देनजर उन्हें बजट में राहत मिलनी चाहिए। इस समय आयकर छूट की जो अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपये है, उसे बढ़ाकर चार लाख किया जाना चाहिए। साथ ही, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत बच्चों की स्कूल-कॉलेज की फीस, बीमा प्रीमियम और विनियोग आधारित लाभ आदि के लिए कटौती की जो सीमा डेढ़ लाख रुपये है, उसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया जाना चाहिए। साथ ही, 10 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की दर 10 फीसदी की जानी चाहिए।

टैक्स की श्रेणियों में भी उपयुक्त बदलाव किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन वर्ग के लोगों के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए छूट की सीमा साढ़े चार लाख रुपये और 80 साल से ऊपर के बुजुगरे के लिए छूट की सीमा 5.5 लाख रुपये की जानी चाहिए। घर खरीदने वालों को मौजूदा 2 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की टैक्स रियायत देनी चाहिए। यह कदम मकान खरीदने वालों को रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आवास क्षेत्र की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। जेटली वर्ष 2018-19 के बजट के माध्यम से जहां छोटे आयकरदाताओं के लिए राहत देते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं नये आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। पिछले एक दशक में लोगों की आय तो तेजी से बढ़ी है लेकिन आयकरदाताओं की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, और छोटे आयकरदाताओं को अपेक्षित राहत नहीं मिली है। हाल में आयकर विभाग ने आयकरदाताओं से संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार 2014-15 में 3.65 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया था। फिर 2015-16 में कुल 4.07 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और 2016-17 में 6.26 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। यद्यपि आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या नोटबंदी के बाद तेजी से बढ़ी लेकिन वास्तविक रूप से आयकर चुकाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रही। वर्ष 2016-17 में 125 करोड़ लोगों में से करीब ढाई फीसद लोगों ने ही आयकर भरा। वर्ष 2018-19 के नये बजट के तहत कॉरपोरेट टैक्स की दर कम किए जाने की संभावना है। यह टैक्स हमारे देश में सबसे ज्यादा है, और अभी ग्लोबल लेवल पर अमेरिका से लेकर जापान तक में कॉरपोरेट टैक्स कम हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में कॉरपोरेट टैक्स घटाने का वादा किया था। लेकिन, उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। चूंकि कम कॉरपोरेट टैक्स रेट से अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, और नौकरियां पैदा होती हैं। अतएव निवेश का वातावरण सुधारने के लिए नये बजट में अरुण जेटली द्वारा कॉरपोरेट टैक्स दरें 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की जा सकती है। वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्त मंत्री पूंजी बाजार को लेकर कई कदमों की घोषणा कर सकते हैं। अन्य निवेश साधनों की तरह इनमें सूचीबद्ध शेयरों में अल्पावधि पूंजी लाभ कर की अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। चूंकि देश के छोटे उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न छोटे उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है, अतएव लघु उद्योगों को टैक्स में छूट दी जा सकती है। इसमें सरकार नये कर्मचारियों को भर्ती करने पर तीन से पांच साल के लिए 30 फीसद की अतिरिक्त छूट दे सकती है, जो किसी भी लघु उद्योग के लिए बड़ी राहत होगी। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रोजगारपरक लघु उद्योग शुरू करने वाले को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विश्व भर में टैक्स रेट कम हो रहे हैं, ऐसे में हमारे देश में भी टैक्स की दरें कम होनी चाहिए अन्यथा हमारा निवेश बाहर चला जाएगा। निस्संदेह वित्त मंत्री के लिए विभिन्न वगरे के लिए कर राहत देना कोई सरल काम नहीं है। कर घटाने का देश के सरकारी खजाने पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि 2017-18 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत रखा गया है, जो इस स्तर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही 2018-19 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 3 प्रतिशत तक रखने के लक्ष्य को पाना भी मुश्किल है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ रही है। आशा करें कि ऐसी वित्तीय चुनौतियों के बीच भी वित्त मंत्री विभिन्न वगरे की कर राहत की अपेक्षाओं के मद्देनजर वित्तीय तालमेल के साथ वर्ष 2018-19 का जो नया बजट प्रस्तुत करेंगे वह छोटे आयकरदाताओं, नौकरीपेशा मध्यम वर्ग एवं उद्योग-कारोबार को राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को विकास की डगर पर आगे बढ़ाने वाला होगा।

चलते चलते

क्राइम भी कहां रुक रहा है?

दिल्ली में सीलिंग ना रुक रही जी! वैसे तो क्राइम भी कहां रुक रहा है? चेन स्नैचिंग कहां रुक रही है? डाके, चोरियां कहां रुक रहे हैं? बलात्कार कहां रुक रहे हैं? पर वो तो पब्लिक के मामले में हैं। चलते रहते हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि यह सरकार,जो चल रहा है चलने दो की फिलॉसफीवाली सरकार नहीं है। पर सीलिंग भी कहां रुक रही है? आप पार्टी सरकार में है और वह सीलिंग के खिलाफ है। भाजपा तो खैर सरकार में है ही है और वह भी सीलिंग के खिलाफ है। कांग्रेस विपक्ष में है सो तय है कि वह सीलिंग के खिलाफ है। पर सीलिंग नहीं रुक रही। दुकानदार सीलिंग के खिलाफ हैं। बाजार, व्यापारियों के संगठन सब खिलाफ हैं। पर सीलिंग नहीं रुक रही। सीलिंग न हुई साहब, भ्रष्टाचार हो गया कि

सरकार,जो चल रहा है चलने दो की फिलॉसफीवाली सरकार नहीं है। पर सीलिंग भी कहां रुक रही है? आप पार्टी सरकार में है और वह सीलिंग के खिलाफ है। भाजपा तो खैर सरकार में है ही है और वह भी सीलिंग के खिलाफ है। कांग्रेस विपक्ष में है सो तय हैं।

रुक ही नहीं रहा। सीलिंग न हुआ, काला धन हो गया कि पैदा होना रुक ही नहीं रहा। आपवाले कह रहे हैं कि हम नहीं करा रहे जी सीलिंग, पूछो शायद भाजपा करा रही हो। भाजपावाले कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल भी नहीं करा रहे, यह जरूर आपवाले करा रहे होंगे। कांग्रेस का मन करता है कि कह दें कि दोनों मिलकर करा रहे हैं। सब सीलिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सीलिंग है कि रुक ही नहीं रही। पानी भी रुक जाता है। पता चलता है कि हरियाणावालों ने नहीं दिया या यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई सो पानी रुक गया। हवा भी रुक जाती है। बिजली नहीं है जी। और तो और राजनीतिक पार्टियों की हवा भी चलते-चलते आखिर में रुक ही जाती है। पर सीलिंग ना रुक रही जी! दुकानदारों, व्यापारियों ने बाजार बंद करके देख लिया। हड़ताल करके देख ली। नहीं रुक रही। हर हफ्ते बस यही खबर आती है कि अगले हफ्ते से सीलिंग और तेज होगी। इस बाजारवाले उस बाजारवालों को कह रहे हैं आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। दुकानदारों ने प्रार्थना करके देख लिया। कई तो पांव भी पड़ लिये। पर सीलिंग का दिल नहीं पसीज रहा। सीलिंग न हुई, महाजन का लठैत हो गई। मान ही नहीं रही। कौन किससे कहे कि इसे रोको? कई बार सरकार का बड़ा मन करता है कि बिल ले आए और सीलिंग रोक दें। पर कहते हैं कि डर रही है कि फिर कहीं दिल्ली स्लम ही न बन जाए!

फोटोग्राफी...

यहां झील के बीच बने 363 वर्ष पुराने चर्च को शुभ मानते हैं शादी करने वाले युगल

यह फोटो यूरोपीय देश स्लोवेनि या की मशहूर 'ब्लेड लेक' का है, जो पहाड़ों से बहकर आने वाले ग्लेशियर के पानी से निंमित हुई है। यहां के पहाड़ों को जुलियन एल्प्स का हिस्सा कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत विशाल है। करीब दो किमी लंबी और डेढ़ किमी चौड़ी यह झील यहां प्रमुख पर्यट न स्थल है क्योंकि इसके ठीक बीच में आइलैंड है, जहां प्राचीन चर्च है। उसका निर्माण संभवत: 1655 मेंकिया गया था। आज इस चर्च में शादि यां आम बात है क्योंकि मान्यता है कि जो दूल्हा अंगूठी पहनाने के पहले यहां पत्थर की बनी 99 सीढ़ीयों पर चढ़कर पहुंचता है, उनका भाग्य संवर जाता है। लोग नौका विहार करके यहां तक पहुंचते हैं। वर्ल्ड रोविंग चैंपियनशिप भी यहां हो चुकी है, जिसके बाद इसे दुनियाभर में पहचान मिली। travelwithpedro.com

''अच्छे दिन' की गूंज सुनाई दी

सान अन्नदाता अवश्य है परंतु आज स्वयं खस्ताहाल है। वर्ष 2014 में गांव-गांव में ''अच्छे दिन' की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसान की आमदनी दोगुना करेगी। लेकिन सचाई यह है कि इन वर्षो में खेती से आय घटी है। कृषि क्षेत्र में अगले 4 वर्षो में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर और समर्थन मूल्यों में 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर देकर ही कृषि क्षेत्र से किसान की आय को लगभग दोगुना किया जा सकता है। लेकिन सत्यता यह है कि किसान की आमदनी का वर्तमान स्तर भी बना रहेगा, यह कहना कठिन है। प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में किसान का सहारा फसल बीमा योजना थी। वर्तमान एकीकृत फसल बीमा योजना से किसान परेशान है। यह योजना किसान के बजाय कंपनियों के हितों को देखकर बनाई गई है। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि में केंद्र सरकार का अंशदान घटने से कृषि क्षेत्र में निवेश घटा है। मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का सहारा न हों तो छोटा किसान और बटाईदार भूखे मर जाएंगे। वर्ष 2016-17 के यूनियन बजट में खेती से आय दुगुना करने की योजना की घोषणा हुई थी, और आज वर्ष 2018-19 में सरकार को सफाई देनी पड़ रही है कि सरकार का लक्ष्य खेती से किसान की आय को दुगुना करना नहीं है, बल्कि किसान की सकल आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप, स्टार्ट अप, मुद्रा, मेड इन इंडिया के सारे दावे बढ़ती बेरोजगारी के सामने सच नहीं माने जा सकते। अमीरों की अमीरी जरूर बेतहाशा बढ़ी है। दावोस के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में प्रस्तुत एक पिंट के अनुसार भारत के एक प्रतिशत अमीरों ने वर्ष 2017 में भारत में कुल पैदा संपदा के 73 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा जमाया है। पैंसठ करोड़ लोगों के हिस्से कुल उत्पादित संपदा का 1 प्रतिशत हिस्सा आया है। अमीरों के पक्ष में यह वृद्धि 1997 की तुलना में लगभग ढाई गुनी है। पिछले 3 वर्षो में देश के कॉरपोरेट सेक्टर को जो छूट दी गई, उनका एक तिहाई हिस्सा यदि किसानों को सार्वभौम ऋणमाफी के तौर पर दिया गया होता तो कृषि क्षेत्र में अच्छा सुधार दिखाई देता। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर पर्यावरणीय परिवर्तनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा जारी एक दस्तावेज के अनुसार भारत इन्क्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में उभरती हुई 79 अर्थव्यवस्थाओं में बासठवें स्थान पर है। दो साल पहले साठवें स्थान पर था। इस इंडेक्स का निर्धारण देश के लोगों के जीवन स्तर, कर्ज ग्राह्यता और पर्यावरणीय संवेदनाओं के आधार पर होता है। चीन और पाकिस्तान इस इंडेक्स में पच्चीसवें और सैतालीसवें स्थान पर है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। इन देशों ने कृषि एवं शिल्प, दोनों में पर्याप्त सुधार किए हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका ने ग्रामीण क्षेत्र में माइक्रो लैंडिंग सुविधाओं को बहुत बढ़ाया है। उसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर उनके नागरिकों के जीवन स्तर पर दिखाई देता है। हमें किसानों की चुनौतियों का राजनीतिकरण के बजाय राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंझोला किसान-छोटा किसान, छोटा किसान-सीमांत किसान होता जा रहा है। हम कृषि प्रधान देश हैं परंतु किसान प्रधान देश नहीं हैं। इसलिए किसान दूर क्षितिज में तांकता हुआ अपने से सवाल कर रहा है। क्या सचमुच अच्छे दिन आ रहे हैं, यदि हां, तो अभी कितनी दूर हैं?

मुख्य कारोबार समाचार

महिलाओं के लिए 8% हुआ PF कॉन्ट्रीब्यूशन, 8 करोड़ को मुफ्त LPG

नई दिल्ली। सरकार ने इस बार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा। जेटली ने कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए जॉब के शुरुआती तीन सालों तक पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया। सरकार के इस फैसले से महिलाओं की इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा। साथ ही बजट में गरीब महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया। सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का एलान किया गया है। यह लक्ष्य पिछले साल 5 करोड़ महिलाओं तक उज्जवला योजना का लाभ पहुंचाने का था।

इन दोनों कदमों के अलावा सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही है। वित्त मंत्री जेटली ने घोषणा की है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। यह प्रावधान मार्च 2019 तक रहेगा।

स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को पुनर्गठित करेगी सरकार

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को पुनर्गठित करेगी और बहुमूल्य धातु पर वृहद योजना लेकर आएगी। उन्होंने आज वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना को पुनर्गठित करने से लोग बिना किसी बाधा के स्वर्ण जमा खाते खोल सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में नियमन वाले स्वर्ण एक्सचेंजों के लिए उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार दक्ष प्रणाली स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सोने को संपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए सरकार एक वृहद स्वर्ण नीति बनाएगी। सरकार ने 2015 में स्वर्ण मौद्रिकरण योजना शुरू की थी। इसका मकद परिवारों और संस्थानों में पड़े सोने को बाहर लाना था। इस योजना के तहत उपभोक्ता घर में बेकार पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिए बैंकों के पास जमा करा सकते है। इस पर उन्हें 2.25 से 2.50 प्रतिशत का ब्याज मिलता है।

मारुति की बिक्री जनवरी में बढ़ी, 1,51,351 वाहन बेचे

नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की कुल बिक्री 4 प्रतिशत बढ़कर जनवरी में 1,51,351 वाहन रही। जनवरी 2017 में कंपनी की बिक्री 1,44,396 वाहन थी। मारुति सुजुकी इंडिया के बयान में कहा कि कंपनी की घरेलू बिक्री 5 प्रतिशत बढ़कर जनवरी में 1,40,600 वाहन रही जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 1,33,934 वाहन था। कंपनी का निर्यात जनवरी 2018 में 2.8 प्रतिशत बढ़कर 10,751 वाहन रहा। पिछले साल निर्यात 10,462 इकाई था। समीक्षाधीन अवधि में आल्टो और वैगन आर समेत छोटी कारों की बिक्री 12.2 प्रतिशत गिरकर 33,316 वाहन रही जबकि जनवरी 2017 में बिक्री 37,928 वाहन थी।

बजट 2018: शेयर से कमाई पर LTCG टैक्स

स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद, PSU बैंक टूटे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगाने के एलान के बाद मार्केट में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 59 अंक टूटकर 35906 और निफ्टी 10 अंक टूटकर 11010 के स्तर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 215 अंक तक मजबूत हुआ था। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स के एलान से मार्केट ऊपरी स्तरों से 700 अंक तक टूट गया। वहीं, अंतिम घंटों में बाजार में रिकवरी रही। फिलहाल ट्रेडिंग के अंत में मार्केट लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

बजट में शेयर से 1 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली कमाई पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का एलान किया गया है। सरकार अभी शेयर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि 1 साल बाद शेयर बेचने पर अगर 1 लाख रुपए का पूरे साल में मुनाफा होता है तो इस पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। अभी 1 साल से कम समय में शेयर बेचने पर 15 फीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

FY 18 के लिए फिस्कल डेफिसिट 3.5%

सरकार ने FY 18 का फिस्कल डेफिसिट 3.5 फीसदी रहने का लक्ष्य रखा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 3.2 फीसदी या नीचे रखा होता तो मार्केट के लिए यह पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन 3.5 फीसदी का टारगेट मार्केट को निराश करने वाला है।

निफ्टी पर 11 में से 8 इंडेक्स में गिरावट

निफ्टी पर 11 में से 8 इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स, मेटल और फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.30 फीसदी, फार्मा इंडेक्स में 2.44 फीसदी की गिरावट है। रियल्टी इंडेक्स 0.81 फीसदी गिरावट है। मेटल इंडेक्स में 0.14 फीसदी, एफएमसीजी इंडेक्स में 0.83 फीसदी और ऑटो इंडेक्स में 0.70 फीसदी की तेजी रही है। और एलएंडटी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचसीएल टेक, आईआईएफएल, अवंति फीड्स, एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी है। वहीं, एनटीपीसी, इंफोसिस, डॉ रेड्डी और वेदांता लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है।

एग्री स्टॉक्स में 5% तक तेजी

बजट भाषण शुरू होते ही एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े शेयरों में अच्छी तेजी आ गई। एस्कॉर्ट्स, दीपक फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर के शेयरों में तेजी दिख रही है। एस्कॉर्ट्स में 5 फीसदी से ज्यादा और जीएसएफएस में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिख रही है।

बैंकिंग सेक्टर में बरकरार नहीं रही तेजी

बजट से ठीक पहले सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी दिख रही थी। पीएनबी, एसबीआई और इंडियन बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों के शेयर बढ़े थे। इंडियन बैंक में 3.05 फीसदी, एसबीआई में 1.35 फीसदी, बैंक ऑफ इंडिया में 1.05 फीसदी और पीएनबी में 1.55 फीसदी की तेजी देखी जा रही थी। लेकिन कारोबार के दौरान सभी शेयरों में बिकवाली आ गई।

मिडकैप शेयरों में गिरावट

मिडकैप शेयरों में थोड़ा दबाव है, लेकिन स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.2 फीसदी गिरा है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी मजबूत हुआ है। मिडकैप शेयरों में एक्साइड, रिलायंस कम्युनिकेशंस, टीवीएस मोटर, आदित्य बिड़ला फैशन और कैस्ट्रॉल 2.5-0.9 फीसदी तक गिरे हैं। हालांकि मिडकैप शेयरों में सीजी कंज्यूमर, इंडियन होटल्स, एसजेवीएन और जीएमआर इंफ्रा 3.1-1.8 फीसदी तक बढ़े हैं।

ये शेयर 52 हफ्तों के टॉप पर

बजट के दिन एलएंडटी, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया बुल्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आरआईएल, भारत फोर्ज, कोटक बैंक, डॉबर, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी और एचयूएल के शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई पर कारोबार कर रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल सस्ते नहीं होंगेः एडिशनल एसाइज ड्यूटी खत्म लेकिन 8% रोड सेस लगाया

एक्साइज ड्यूटी करके सरकार ने हैरान करने वाला कदम उठाया है। दरअसल, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए कम कर दी। लेकिन 8% रोड सेस लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल दो रुपए सस्ते हो गए हैं। लेकिन इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। बाद में जेटली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने कहा- एक्साइज ड्यूटी कम करके इसे सेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन, इसका फायदा सीधा कस्टमर्स को नहीं मिलेगा।

पिछले साल घटाई गई थी एक्साइज ड्यूटी

जेटली ने बजट में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर कम करने का एलान किया। कुछ दिनों पहले ऑयल मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर कहा था कि एक्साइज ड्यूटी अब कम की जानी चाहिए। बता दें कि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए हो चुकी है। ये रिकॉर्ड हाई है। सरकार ने ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों तरह के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में आखिरी बार एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। तब पेट्रोल का दाम देश भर में करीब 80 रुपए प्रति लीटर होने वाला था।

सरकार पर बोझ बढ़ेगा

एक्साइज ड्यूटी करके सरकार ने हैरान करने वाला कदम उठाया है। दरअसल, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है। इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं। फिलहाल, ब्रेंट क्रूड ऑयल 68 डॉलर प्रति बैरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रेट आने वाले दिनों में 80 या 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। यानी सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। तीन साल पहले जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई थीं तब सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए और डीजल पर 13.77 रुपए बढ़ाकर अपना खजाना भर लिया था।

जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा

इकोनॉमिक सर्वे 2018 में कहा गया था कि क्रूड ऑयल अगर 10 डॉलर प्रति बैरल की रफ्तार से इसी तरह बढ़ता रहा तो जीडीपी को इससे 0.2 से 0.3% का हर साल नुकसान होगा। और इससे वित्तीय घाटा भी 9 से 10 बिलियन हर साल बढ़ जाएगा।

बजट 2018 : रेलवे को मिलेंगे 1.48 लाख करोड़, 3600 KM पटरियों का होगा नवीकरण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे को पूरी तरह ब्रॉडगेज किया जाएगा। इसके अलावा पटरी लेकर उनकी सरकार का पहला लक्ष्य सुरक्षा है। जेटली ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल बजट का बड़ा हिस्सा पटरी और गेज बदलने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा।

700 नए रेल इंजन और 5160 नए कोच

5000 किलोमीटर लाइन के गेज परिवर्तन का काम चल रहा है। वित्त मंत्री ने बताया, 'छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने काम पूरा किया जा रहा है। इस दिशा में पूरी तेजी से काम कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि इस साल 700 नए रेल इंजन और 5160 नए कोच तैयार किए जाएंगे। सुरक्षा के इंतजामों पर बात करते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने की योजना का भी एलान किया है। उन्होंने बताया कि इस साल में 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के अलावा स्टेशनों पर ऐस्केलेटर्स बनाने की भी योजना है।

3600 किमी ट्रैक का नवीकरण

वित्त मंत्री ने बताया कि रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 3600 किमी ट्रैक का नवीकरण किया गया। 40000 करोड़ रुपये एलिवेटेड कॉरिडर के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। मुंबई रेलवे को शहर की लाइफलाइन बताते हुए मुंबई लोकल का दायरा 90 किलोमीटर बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं मोदी सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना बुलेट ट्रेन पर घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाने का काम शुरू करने के लिए जो भी इस संबंध में जरूरी है उसे पूरी करेंगे।

रेलवे में पिछले साल हुए थे ये एलान

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल के बजट में रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया था। जबकि 2015 में यह आंकड़ा 1.21 लाख करोड़ रुपए था। 2017 के आम बजट में रेलवे के जिन 4 सेक्टर पर फोकस किया गया था वो - पैसेंजर सेफ्टी, स्वच्छता, कैपिटल एंड डेवलपमेंट वर्क और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिफॉर्म रहे।

बजट 2018 : जाने बजट की महत्वपूर्ण बातें, पर्सनल इनकम टैक्स रेट में बदलाव नहीं

सीनियर सिटीजंस को 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्स रेट और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मोर्च पर कई तरह की बड़ी सहूलियत दी है।

इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री ने आम बजट 2018 में इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स के लिए बजट 2017 का टैक्स स्लैब ही प्रभावी होगा।

2018-19 के लिए टैक्स स्लैब

इनकम स्लैब	टैक्स रेट
2.5 लाख रुपए तक	0
2.5 से ज्यादा- 5 लाख तक	5%
5 लाख से ज्यादा-10 लाख	20%
10 लाख से अधिक	30%

नहीं कर सकेंगे 10,000 से ज्यादा की कैश पेमेंट

आम बजट में कहा गया है कि 10,000रु रुपए से अधिक की कैश पेमेंट की अनुमति नहीं होगी। यानी अब कोई भी कंपनी या ट्रस्ट 10,000 रुपए से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया है।

लॉन्ग टर्म गैपिटल गैन टैक्स में बदलाव, 1 लाख के ज्यादा के रिटर्न पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा

शेयर बाजार में एक साल निवेशित रहने के बाद अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है तो उस पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन लगेगा। यह टैक्स 10 फीसदी की दर से लगाया जाएगा। अभी तक एक साल से ज्यादा होने वाली पूरी कमाई टैक्स फ्री होती थी।

* मोबाइल फोन लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की
* स्मार्टवाचेस, वियरेबल डिवाइसेज पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी की
* इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 20 फीसदी की
* फुटवियर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी की
* ट्रक और बसों के रेडियल टायर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की
* पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा
* सोना-चांदी के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज
* पोलिस्ड कलर्ड स्टोन होंगे सस्ते, इंपोर्ट ड्यूटी 5 से घटकर 2.5 फीसदी हुई
* अनब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.33 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर की
* भारत ने काफी हद तक हासिल किया फिस्कल डेफिसिट का टारगेटः मूडीज
* पेट्रोलियम सब्सिडी 24,930 करोड़ रुपए रहने का अनुमान
* वित्त वर्ष 2018-19 में कॉरपोरेशन टैक्स 6.21 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान
* फर्टिलाइजर सब्सिडी 70,100 करोड़ रुपए रहने का अनुमान
* कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए 63,836 करोड़ रुपए का आवंटन
* गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं
* डिफेंस के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
* वित्त वर्ष 2018-19 में GST कलेक्शन 7.44 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान
* वित्त वर्ष 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट GDP का 2.2 फीसदी रहने का अनुमान
* नॉमिनल GDP ग्रोथ 11.5 फीसदी रहने का अनुमान
* ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 22.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
* वित्त वर्ष 2018-19 में ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 6.06 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
* नेट मार्केट बॉरोइंग 4.62 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य
* कुछ सामान के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया गया
* चुनिंदा आइटम्स पर बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी
* मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, 15 से बढ़ाकर की हुई 20 फीसदी
* टीवी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की
* रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी की
* म्युचुअल फंड डिविडेंड पर 10% टैक्स
* हेल्थ, एजुकेशन सेस से सरकार को मिलेगा 11 हजार करोड़ रु रेवेन्यू
* लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू
* हेल्थ एजुकेशन सेस बढ़ाकर किया 4 फीसदी
* शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं, बना रहेगा 15 फीसदी
* 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म गेन्स
* लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मामूली बदलाव का प्रस्ताव
* LIC की सीनियर सिटीजंस के लिए 8 फीसदी एश्योर्स इनकम प्लान्स 2020 तक के लिए एक्सटेंड
* स्टैंडर्ड डिडक्शन से सरकार को 8,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का होगा नुकसान
* सीनियर सिटीजंस को 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर एग्जम्प्शन
* MSME को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से 7,000 करोड़ रु घटेगा सरकार का रेवेन्यू
* इनकम टैक्स में 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मंजूरी
* कॉरपोरेट टैक्स में कमी से 99 फीसदी MSME को मिलेगा फायदा
* पर्सनल इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
* 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 25% कॉरपोरेट टैक्स
* ब्लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए उठाए जाएंगे कदम
* टैक्स चोरी रोकने के कदमों से मिला 90 हजार करोड़ रु का अतिरिक्त टैक्स
* GDP की तुलना में कर्ज के अनुपात को 40 फीसदी तक घटाने का लक्ष्य
* कृषि उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को टैक्स राहत की घोषणा
* रियल्टी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम आसान किए गए
* वित्त वर्ष 2017-18 का कुल संशोधित व्यय 21.57 लाख करोड़ रुपए
* FY 18 का फिस्कल डेफिसिट 3.5 फीसदी होगा
* FY 19 का फिस्कल डेफिसिट 3.35 फीसदी होगा
* अमरुत योजना के तहत 500 शहरों में सभी घरों को की जाएगी वाटर की सप्लाई
* दिए जाएंगे 19428 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट
* नए रूप में लाई जाएगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
* गोल्ड को एसेट क्लास में तब्दील करने की पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार
* हाइब्रिड फाइनेंसियल इंस्ट्रुमेंट्स के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी सरकार
* राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपित की सैलरी 4 लाख रु होगी
* MP का सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होगा
* MP की सैलरी, भत्ते के लिए 5 साल का सिस्टम लागू
* नया सिस्टम 1 अप्रैल 2018 से लागू
* पब्लिक सेक्टर की 3 इन्श्योरेंस कंपनियों को मर्ज कर बनाई जाएगी एक कंपनी
* वित्त वर्ष 18 का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिवाइज करके किया 1 लाख करोड़ रु
* मार्केट से फंड जुटा सकेंगे रीजनल रूरल बैंक
* डेट बेस्ड ETF सहित अन्य ईटीएफ के लिए तलाशी जाएंगी संभावनाएं
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 372 रिफॉर्म की पहचान की गई
* डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी बनाएगी सरकार
* हर एंटरप्राइजेज को एक यूनीक आईडी देगी सरकार
* वित्त वर्ष 2018-19 में इन्फ्रा पर खर्च होंगे कुल 5.97 लाख करोड़ रुपए
* आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस R&D के लिए योजना बनाएगा नीति आयोग
* डिजिटल इंडिया प्लान के लिए 3,073 करोड़ रुपए का आवंटन
* अगले साल से इनवेस्ट ट्रस्ट के जरिए PSU को किया जाएगा मोनेटाइज
* गिफ्ट सिटी के लिए बनाया जाएगा यूनिफाइड फाइनेंशियल मार्केट रेग्युलेटर
* क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए कदम उठाएगी सरकार
* इस साल 700 नए रेलवे इंजन बनाए जाएंगे
* रूरल कनेक्टिविटी के लिए लगाए जाएंगे 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट
* बेंगलुरू में सबअर्बन रेल इन्फ्रा के लिए 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन
* जल्द ही सभी ट्रेनों में लगेगा वाई-फाई सिस्टम, लगेंगे सीसीटीवी
* 2 साल में खत्म की जाएंगी 4267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग
* रेल ट्रैक के रखरखाव पर खास ध्यान देगी सरकार
* 3600 किमी रेल पटरियों को नया बनाया जाएगा
* उड़ान स्कीम के तहत 37 नए हैलीपैड जुड़ेंगे
* आलू-प्याज के ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च
* सस्ती दरों पर सोलर पंप मुहैया कराएंगे
* रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित
* 10 जगहों को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में करेंगे तब्दील
* स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए का एलान
* 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग मिलेगी
* सेला पास के नीचे होगा सुरंग का निर्माण
* टैक्सटाइल सेक्टर के लिए 7150 करोड़ रु का ऐलान
* महिला कर्मचारियों के EPF में 3 साल तक 8 फीसदी का योगदान करेगी सरकार
* ST के लिए 39,135 करोड़ रु का आवंटन
* सरकार की योजना अहम हिस्सा है जॉब क्रिएशनः जेटली
* स्टार्टअप फंड के लिए माहौल सुधारने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम
* GSTN के साथ ई-ट्रेड रिसिवेबिल्स प्लेटफार्म किया जाएगा लिंक, PSU भी बनेंगे इसका हिस्सा
* मुद्रा योजना के तहत रिफाइनेंस फैसिलिटी को रिव्यू करेगी सरकार
* सौभाग्य योजना के तहत बांटे जाएंगे 4 करोड़ बिजली कनेक्शन
* वित्त वर्ष 2019 तक मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रु के लोन बांटने का लक्ष्य
* MSME के लिए ऑनलाइन लोन फैसिलिटी में होगा सुधार
* MSME की बैड लोन्स की समस्या दूर करेगी सरकार
* MSME क्रेडिट सपोर्ट के लिए 3794 करोड़ रुपए का आवंटन
* SC वेलफेयर के लिए 56620 करोड़ रुपए का आवंटन
* पीएम इन्श्योरेंस योजना के दायरे में आएंगे सभी गरीब परिवार
* गंगा सफाई अभियान के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
* 60 करोड़ जनधन अकाउंट को मिलेगा माइक्रो इन्श्योरेंस का बेनिफिट
* मौजूदा हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके खोले जाएंगे ये मेडिकल कॉलेज
* हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना
* इस वित्त वर्ष में खोले जाएंगे 24 मेडिकल कॉलेज
* टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रु का आवंटन
* स्वास्थ्य योजना में प्रति परिवार मिलेगा 5 लाख रु का बीमा कवर
* यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार
* गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च
* 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
* हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन
* बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च, हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा
* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
* अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रा पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
* पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए फसलों के अवशेष को करेंगे रिसाइकिल
* स्त्र छात्रों के लिए बनेंगे एकलव्य स्कूल
* प्री-नर्सरी से 12वीं तक के एजुकेशन सिस्टम में होगा सुधार
* मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड
* सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 9975 करोड़ रुपए का आवंटन
* राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रु का आवंटन
* रूरल इन्फ्रा के लिए 14.3 लाख करोड़ रुपए आवंटन
* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
* नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना
* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
* सस्ता घर योजना के तहत गांवों में 51 लाख घर बनाने की योजना
* 2022 तक सभी गरीबों को घर देने का लक्ष्य
* इस वित्त वर्ष 2 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य
* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन
* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन
* वित्त वर्ष 2019 में किसानों 11 लाख करोड़ रु का कर्ज देगी सरकार
* दिल्ली में पॉल्युशन से निबटने के लिए बनेगी अलग स्कीम
* मछली पालन के लिए बनाए जाएंगे कुल 10 हजार करोड़ के बनेंगे 2 फंड
* पशुपालन और मछली पालन के लिए भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड
* फार्म एक्सपोर्ट के लिए 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
* फार्म कमोडिटीज के निर्यात के नियमों को उदार बनाया जाएगा
* फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन
* ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन की करेंगे शुरुआत
* दवाओं से जुड़ी फसलों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन
* आर्गेनिक फार्मिंग के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करेंगे
* होर्टीकल्चर फसलों के लिए क्लस्टर बेस्ड मॉडल होगा डेवलप
* E-NAM को APMC रेग्युलेशंस से छूट मिलेगी
* 470 APMC को मार्च तक e-NAM से जोड़ा जाएगा
* 22 हजार रूरल हाट्स बनेंगे एग्रीकल्चर मार्केट
* फार्म डेवलपमेंट फंड के लिए 2000 करोड़ रु के फंड का आवंटन
* किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, नीति आयोग तैयार करेगा सिस्टम
* MSP में बढ़ोत्तरी पर्याप्त नहीं, किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए
* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना
* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा
* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद
* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम
* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम
* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर
* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम
* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा
* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना
* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर
* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान
* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत
* जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत
* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी
* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ
* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल
* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट
* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत
* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल
* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई
* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना
* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा
* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद
* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम
* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम
* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर
* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम
* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा
* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना
* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर
* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान
* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत
* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी
* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ
* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल
* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट
* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत
* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल
* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई

ई-वे-बिल की जानकारियों के लिए एनटीएम बोर्डरूम में सेमिनार

अधिकारियों ने फोस्टा व व्यापारियों को दी ई-वे-बिल की जानकारी

संवाददाता. सूरत। फोस्टा पदाधिकारियों और न्यू टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों व अन्य कपड़ा मार्केट के व्यापारियों की ओर से एनटीएम के बोर्डरूम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ एनफोर्समेंट मितेश प्रजापति डिवीजन-7, डिप्टी कमिश्नर ऑफ एनफोर्समेंट पीएम देसाई डिवीजन-8, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेट सेल हितेश जालुजी के साथ एक फरवरी गुरूवार से लागू होने वाले ई-वे-बिल के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई-वे-बिल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने व आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सेमिनार के माध्यम से जानकारी दी गई। मितेश प्रजापति ने व्यापारियों को ई-वे-बिल की प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में आयोजित व्यापारियों ने बारी-बारी से अपनी समस्याओं को रखा और समस्याओं के समाधान के लिए मांग की। व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। सेमिनार में फोस्टा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सरदार अत्तर सिंह, बजरंगभाई खंडेलवाल, दीपचंद चौधरी, चंपालाल बोथरा सहित काफी तादाद में फोस्टा पदाधिकारी व कपड़ा व्यापारी मौजूद थे।

ओपन हाउस में करदाताओं ने सुनाई समस्या

संवादाता, सूरत। मजूरा गेट स्थित आयकर भवन में ओपन हाउस का आयोजन बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया। ओपन हाउस में शहर के काफी तादाद में हीरा व्यापारी व कपड़ा व्यापारी पहुंचे और अपनी समस्याओं से मुख्य आयकर आयुक्त अजय दास मल्होत्रा को अवगत कराया। आयकर दाताओं की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया। ओपन हाउस में मुख्य आयकर आयुक्त ने विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए आयकर विभाग में सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को आदेश दिए।

बढ़ाया गया प्रोसेसिंग जॉब चार्ज नहीं हुआ लागू

अपने निजी निर्णय से पीछे हटे फोसेसर्स

संवाददाता, सूरत। दक्षिण गुजरात प्रोसेसर्स एसोसिएशन की ओर से एक फरवरी से प्रोसेसिंग जॉब चार्ज में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को लागू करने के निर्णय को वापस ले लिया है। पिछले महिने पांडेसरा स्थित दक्षिण प्रोसेसर्स एसोसिएशन के बोर्ड रूम में एक फरवरी से प्रोसेसिंग जार्च में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में प्रोसेसिंग के दौरान लगने वाले केमिकल व अन्य वस्तुओं के दाम में जीएसटी के चलते बढ़ोतरी होने का निर्णय लिया था। वहीं मिल संचालक भवरलाल व गोपाल रिणवा ने कहा कि कारीगरों को वेतन बढ़ाकर देना पड़ रहा है। इसलिए कपड़ा प्रोसेसिंग युनिट की ओर से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए।

इनका कहना है:- कपड़ा मार्केट अभी तक आर्थिक पटरी पर लौट नहीं सका है। इस दौरान प्रोसेसर्स एसोसिएशन की ओर से प्रोसेसिंग जॉब चार्ज बढ़ोतरी करना कपड़ा व्यापारी के लिए दोहरी मार के समान था। फोस्टा की ओर से प्रोसेसर्स एसोसिएशन से बातचीत की गई। फोस्टा के विचार से सहमत होकर प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने अपने प्रोसेसिंग जॉब जार्च को बढ़ाने के निर्णय को वापस ले लिया है। **फोस्टा अध्यक्ष, मनोज अग्रवाल**

गोड़ादरा में अवैध निर्माण पर चला मनपा का हथौड़ा

संवाददाता, सूरत। आसपास मंदिर के समक्ष मुख्य मार्ग पर कई वर्षो से अवैध निर्माण किया हुआ है। जिसे मनपा के तोडू दस्ते ने धराशायीकर दिया। अतिक्रमण हटाते हुए मनपा कर्मी तस्वीर में द्रश्यमान है।

डिंडोली में मानसिक बीमारी से परेशान व्यक्ति ने फांसी लगा दी जान

संवाददाता, सूरत। डिंडोली के करडवा रोड स्थित राजदीप रो-हाउस में मानसिक बीमारी से परेशान होकर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलत: महाराष्ट्र, जलगांव, चोपड़ा, गुमावल गांव के तथा डिंडोली के करडवा रोड स्थित राजदीप रो-हाउस नं. 333 में रहने वाले संजय संतोषभाई चौहाण (45 वर्ष) पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी होने के कारण चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। संजयभाई का इलाज चल रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होने से गत रोज रात 9 बजे के करीब अपने घर में छत में लगे हुक के साथ रस्सी बांधकर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। घटना के संदर्भ में डिंडोली पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

सरथाणा में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर स्वयं भी दे दी जान

संवाददाता, सूरत। सरथाणा की श्यामधाम सोसाइटी में रहने वाली एक महिला द्वारा अपने तीन साल की बेटी को अनाज में रखी जाने वाली टिकिया खिलाकर उसकी हत्या करने के बाद स्वयं भी आत्महत्या कर लेने की समसनी पूर्ण घटना प्रकाश में आई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के सरथाणा क्षेत्र श्यामधाम चौक विभाग-1, श्यामधाम सोसाइटी मकान नं. 255 में रहने वाले जिग्रेश कानजीभाई इटालिया की पत्नी सुमीताबेन जिद्दी स्वभाव की थीं। सुनीता किसी भी बात पर अक्सर जिद करने लगती थी। गत रोज सुनीताबेन ने अपने जिद्दी स्वभाव के कारण अपनी 3 वर्ष की पुत्री आरती को अनाज में डालने वाली टिकिया खिलाकर उसकी हत्या करने के बाद स्वत: भी वही टिकिया खा लिया। जिसको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई। घटना के बारे में सरथाणा पुलिस ने हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

रेलवे लाइन पर घायल हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान मौत

संवाददाता, सूरत। पांडेसरा के प्रमुखपार्क स्थित केबिन के समीप गत रोज देर रात को रेलवे लाइन पर गंभीर रूप से घायल हालत में मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पांडेसरा के प्रमुखपार्क के पीछे स्थित रेलवे केबिन के पास एक करीब 32 वर्षीय युवक किसी ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर हालत में मिला था।

जिसको इलाज के लिए 108 के द्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर क्षणिक इलाज के पाश्चात उसकी मौत हो गई। पांडेसरा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मृत युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

मामूली बोलाचाली होने पर पति ने पत्नी का गला घोंट कर दी हत्या

संवाददाता, सूरत। पूणा कुंभारिया में दोस्तों के साथ घूमने की बात को लेकर पत्नी से मामूली नोकझोंक होने पर पति ने पत्नी की वायर के द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बारे में मृतका की माता द्वारा पूणा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूणा कुंभारिया गुंदी फलिया के घर नं. 309/391 में रहने वाले मंगाभाई उर्फ गांडाभाई बजाणिया अक्र अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमते रहते थे। इस बात को लेकर उनकी पत्नी वरिलबेन से कुछ कहासुनी हो गई। जिससे विरलबेन ने कहा कि मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हूं। विरलबेन की इस बात पर मंगाभाई क्रोध में आ गए और बोले कि तूं क्यों फांसी लगाएगी? मैं ही तुझको फांसी लगा देता हूं। यह कहने के बाद मंगा ने घर में पड़े कूलर के वायर से विरलबेन का गला कसकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होने पर मृतका विरलबेन की माता ने पूणा पुलिस में अपने दामाद के खिलाफ बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है।

प्रदिप सिंघी एण्ड एसोसिएट्स
बजट के महत्वपूर्ण बदलाव
1. नौकरी करने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 40000/-
2. व्यक्तिगत, एच यू एफ आयकर व सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं । सिर्फ एजुकेशन सेस 3% से बढ़ाकर 4% की गयी ।
3. 50 करोड़ से 250 करोड़ तक टर्नओवर वाली कम्पनी का कॉरपोरेट टेक्स 30त्न से 25त्न किया गया ।
4. 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों के लिये बदलाव।

अमरोली के मोटा वराछा से 3.7 लाखी शराब से भरा टेंपो बरामद, चालक फरार

संवाददाता, सूरत। अमरोली पुलिस ने मोटा बराछा मदरसा संकुल के पास टेंपो में 3 लाख 7 हजार रुपए की भरी शराब को बरामद कर फरार हो गए टेंपो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करक मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरोली पुलिस ने मिली गोपनीय सूचना के आधार पर मोटा वराछा मधरेसा संकुल के पास छापा मारकर एक टेंपो से 3,07,200 रुपए की 3072 बोतल बरामद की। जबकि पुलिस को देख टेंपो चालक स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने टेंपो के डिटेल के आधार पर फरार हुए चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही है।

अज्ञात शख्सों ने युवक की चाकू गोदकर की हत्या

अहमदाबाद (ईएमएस)। शहर के ओढव इलाइलाकेक में कुछ अज्ञात शख्सों ने एक युवक की चाकू गोदकर निर्म हत्या कर दी। इस घटना से समग्र इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की है। शहर के पूर्वी इलाके में चोरी, लूट, मारपीट और हत्या जैसी घटनाओं इजाफा हुआ है। सरेआम और दिनदहाडे गंभीर अपराधों से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे है। शहर में हर एक या दूसरे दिन ऐसी गंभीर घटनाएं सामने आ रही है। मनोज नाथुराम वर्मा नामक युवक स्टील की कंपनी में नौकरी कर अपना व परिवार का गुजरान चलाता था।

'सबका साथ सबका विकास' को पूर्ण करने वाला सर्वस्पर्शी बजट: रूपाणी

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया केन्द्रीय बजट का स्वागत

गांधीनगर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा आज प्रस्तुत २०१८-१९ के बजट को सबका साथ, सबका विकास संकल्प साकार करने वाला जनहितकारी, सर्वस्पर्शी बजट करार दिया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यव-स्था को मजबूत करने वाला, किसान, खेती और ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करने वाला तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला बजट है। नया भारत- न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यह बजट अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई जैसे आधारभूत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभकारी साबित होने वाले इस बजट की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आयुष्यमान भारत के फ्लेगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार ५० करोड़ गरीब लाभार्थियों को ५ लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच केन्द्र सरकार प्रदान करेगी। गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान देने वाले इस केन्द्रीय बजट में ४ करोड़ गरीबों को नि:शुल्क बिजली सुविधा तथा ८ करोड़ ग्रामीण माता-बहनों को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलवाने वाली उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की संकल्पबद्धता गरीबों के प्रति केन्द्र सरकार की संवेदना का प्रतिघोष करती है। मुख्यमंत्री ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, ग्रीन हाउस, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्रोत्साहन तथा कलस्टर आधारित खेती तथा प्रत्येक खेत को सिंचाई सुविधा प्रदान करने वाले २६०० करोड़ के प्रावधान-ऑपरेशन ग्रीन की सराहना करते हुए कहा कि किसानों के लिए यह उत्कृष्ट बजट है। रूपाणी ने युवा वर्गों को रोजगार के अवसर, महिलाओं, छोटे एवं मध्यम उद्योगकारों के लिए प्रोत्साहक नीतियों वाले इस बजट को न्यू इंडिया का लक्ष्य साकार करने वाला बजट बताया है।

चुनाव समय के साथी हार्दिक व जिज्ञेश के बीच दरार?

अहमदाबाद (ईएमएस)। विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा सरकार के खिलाफ खड़े होनेवाले आंदोलनकारी नेता हार्दिक व जिज्ञेश के बीच दरार होने की खबरें सामने आ रही है। हार्दिक पटेल द्वारा की गई एक ट्वीट दलितों में नाराजगी फैली हुई है। अब अपने-अपने समाज को लेकर दोनों एकदूसरे के सामने आ गए है। अहमदाबाद जिले के गीतापुर गांव में कुछ गुंडो ने जमीन हथिया लेने पर ग्रामजनों ने विरोध किया। ग्रामजन देत्रोज तहसीलादर की ओफिस के बाहर अनशन कर रहे थे। पांच दलित परिवारों सरकार द्वारा प्लोट आवंटित किया गया था परंतु पजेशन नहीं मिलने के कारण दलित परिवार अनशन कर रहे थे। इसके सामने गांव के पटेल समुदाय के लोग भी अनशन पर बैठ गए और तहसीलदार से मांग की कि प्लोट दलितों को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि यह प्लोट ग्रामपंचायत का है इसलिए दलितों को प्लोट नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले हार्दिक 24 जनवरी को आंदोलन कर रहे पाटीदारों को मिला था। उससे एक दिन पहले जिज्ञेश मेवाणी ने भी दलितों से मुलाकात की और जमीन विवाद समेट लिया गया। इसी बीच हार्दिक ने अनशन कर रहे दलितों को असमाजिक बताते हुए किसी जाति के साथ जोडा नहीं जाना चाहिए। हार्दिक के एस ट्वीट से दलितों में आक्रोश फैल गया। अनशन कर रहे दलितों के अनशन 12 दिनों तक चला था। दलितों के प्रश्न का हल निकालने के बजाय हार्दिक अपने समाज के लोगों को समर्थन देने के लिए उनके पास बैठा था। सरकार द्वारा 2013 में दलितों को जमीन आवंटित करने का वायदा किया गया था। हार्दिक द्वारा ट्वीट से गुस्साए दलितों ने हार्दिक को भागपुरा गांव से भगा दिया। बाद में हार्दिक ने माफी भी मांग ली थी। हार्दिक के ट्वीट से गुस्साए दलितों व जीज्ञेश ने एक मेमोरेन्डम तैयार कर किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए हार्दिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले जीज्ञेश ने कहा कि हार्दिक ने इस मामले माफी मांग ली है। दलितों को सरकार द्वारा जमीन आवंटित करने का वायदा किया है इसलिए आंदोलन समेट लिया गया है। कृषि जमीन को नोन एग्रिकल्चरल लेन्ड में तब्दिल करने की सहमित देने पर सरकार से सहमित हो चुकी है। सरकार ने जमीन पर मकान बनाने का खर्च वहन करने का आश्वासन दिया है। हार्दिक ओर मेरे बीच मतभेद है परंतु भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ खडे रहेंगे। किसी विषय में मेरे विचार अलग हो सकते है और उसे भी असहमत होने का हक है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय हार्दिक ओर जिज्ञेश की दोस्ती बढी थी।

भाजपा सरकार का केन्द्रीय बजट निराशाजनक :कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस)। केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश 2018-19 के केन्द्रीय बजट को कांग्रेस ने सम्पूर्ण निराशाजनक बताया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि 4 वर्ष के कुशासन के चलते गड्ढे में गिरे भारतीय अर्थतंत्र की गति देने के का अभाव बजट में है। बजट में रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाने का अभाव है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पिछले 4 वर्ष से देश का किसान कड़ी मजदूरी कर अनाज, सब्जियां और फल की पसलें पैदा करता है। परंतु वर्तमान सरकार किसान को पर्याप्त समर्थन मूल्य न देकर कृषि उत्पादों को खरीदने में विफल साबित हुई है। कृषि उत्पादों पर डेढ गुना समर्थन मूल्य पर खरीदने का वायदा करनेवाली भाजपा सरकार ने फिर एकबार किसानों को लोलीपोप थमा दी है। वर्तमान समय में भी किसानों को मूंगफली समेत कई पैदावारों के उचित दाम नहीं मिल रहे। कृषि बीमा की योजना सिर्फ निजी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। 21 हजार करोड के प्रीमियम के सामने बीमा कंपनियों को 16 हजार करोड का मुनाफा कराया गया और किसानों को सिर्फ लोलीपोप ही मिली। कृषि बीमा योजनाओं से किसानों को कोई राहत नहीं मिली। 2022 तक किसानों की आय दोगुना बात कनेवाली भाजपा सरकार किसानो की आय आधी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पिछले तीन वर्ष में घरेलू व विदेशी पूंजीनिवेश में काफी कमी आई है। पूंजीनिवेश बढाने वाले रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। देश का मध्यमवर्ग वषी से ईमानदारी का उत्सव मनाता है परंतु वित्तमंत्री ने इन्कमटैक्स भरनेवाली आम नागरिको को कोई सुविधा बजट में नहीं दी है। वित्तीय खाद्य बजट 3.5 प्रतिशत अधिक रहने से महंगाई बढेगी और उसकी मार गरीब व मध्यमवर्ग को झेलनी पड़ेगी। अर्जुन मोढवाडिया ने आगे कहा कि देश में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन करने की जरुरत अधिक थी, परंतु पिछले चार वर्ष से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन न के बराबर हुआ है। गरीब व मध्यमवर्ग शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी सेवाओं पर अधिक निर्भर रहते है. बजट ने इस वर्ग को भी निराश किया है। वित्तमंत्री ने 51 लाख नए घर देना का और 2022 तक गरीबों को मकान देने का लोलीपोप दिया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब 50 लाख घर देने का वायदा किया था परंतु पांच वर्ष में 50 लाख मकान तो दूर की बात है, सिर्फ दो लाख ही मकान दिए है। बडे शहरों में गरीबों को मकान देने देने के नाम पर गरीबों के मकान तोड़कर बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पिछले वर्ष में क्रूड ओइल के दाम में कमी के कारण भाजपा की केन्द्र सरकार ने एक्साइज ओर अन्य टैक्स से 6 करोड से अधिक की आय हुई है। पब्लिक सेक्टर ओइल कंपनियों ने अरबों रुपयों का मुनाफा किया है। इसके बावजूद देश की आम जनता, मध्यमर्ग, बेरोजगार युवा, विद्यार्थी और गृहिणियों को राहत देने में देश के वित्तमंत्री, प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार निष्फल साबित हुई है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com